अवैध निर्माणों की रिश्वत के भाव बढ़े : चोर-उचक्के चौधरी, लुडीरन प्रधान वाली कहावत चरितार्थ

फ़रीदाबाद (म.मो.) चोर-उच्चके चौधरी, लुंडीरन प्रधान वाली कहावत बडखल विधानसभा प्रोपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान नरेश चावला उर्फ़ (कटोरा)व उसके गिरोह पर बिल्कुल सटीक बैठती है।

पिछले दिनों नरेश चावला व उसके बिल्डर साथियों ने एक योजना बना कर प्रोपर्टी डीलर एसोसिएशन का गठन किया व उसका प्रधान नरेश चावला को बनाया। यहां पाठकों को बता दें कि चावला के इस गिरोह में शहर के बिल्डरों के साथ-साथ ऑन लाइन कैसिनो का धंधा व सरकारी जमीनों पर कब्ज़ा कर अवैध निर्माण बनाने वाले सारे शहर के 'मौजिज' बिल्डर लोग शामिल हैं।

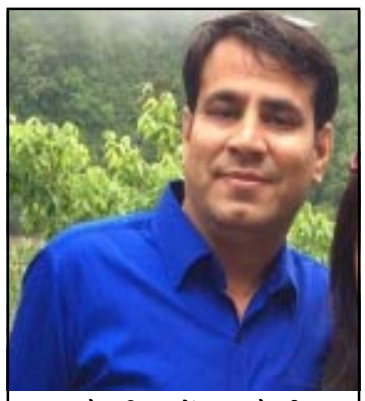

अवैध बिल्डरों का चौधरी नरेश चावला

एसोसिएशन की आड़ में इस गिरोह के कई और भी धंधे हैं जिनका नेतृत्व नरेश चावला बखूबी निभाता है। इस गिरोह में दो-चार बिल्डर ऐसे भी हैं जिन्होंने मार्केट का काफ़ी रुपया भी देना है। अगर लेनदार इन बिल्डरों से तकाजा करता है तो ये बिल्डर उसके साथ मार-पीट करने पर उतारू हो जाते है। ऐसे में प्रधान चावला उन पर पूरे गिरोह के साथ सम्बन्धित थाने में पहुंच कर पुलिस अधिकारी पर अपना दबाव बना कर उल्टा रुपया लेने वाले पर ही मार-पीट करने का आरोप लगाकर फ़ैसला करवा देता है।

इसी गिरोह में कई फ़र्जी पत्रकार भी शामिल हैं। जो नरेश चावला के फ़ोन पर थाने व चौकियों में पहुंच कर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ़ इस गिरोह ने अपनी एसोसिएशन को योजना बनाकर रजिस्ट्रेशन करवा कर अगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में भी नेताओं से रुपया ऐठने का मन भी बना लिया है।

यहां पाठकों को बता दें कि इस एसोसिएशन में ज़्यादातर प्रोपर्टी डीलर रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। एनएच 5 के हर गली मोहल्ले में इनके अवैध निर्माण जारी हैं। एनआईटी 5 के एम ब्लॉक व केसी रोड पर भी प्रधान नरेश चावला व उनके मिलने वालों के अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है।

सूत्रों अनुसार इन अवैध निर्माणों में वार्ड नम्बर 14 के पार्षद सरदार जसवंत सिंह ने अभी हाल ही में बिल्डरों व नरेश चावला से सैटिंग कर अवैध निर्माण बनाने की खुली छूट भी दी है।

अपने शुरूआती दौर में नरेश चावला एक कबाड़ी था व उसके बाद नीलम बाटा रोड पर स्थित महालक्ष्मी होटल के मालिक प्रेम के सम्पर्क में आते ही के सी रोड पर इससे लाटरी बाजार कई वर्ष तक चलाया व उसके बाद थाना प्रभारी अनिल कटारिया के साथ मिल कर कई मोटी दलाली के काम कर आज प्रोपर्टी डीलर एसोसिएशन का प्रधान बना है।

एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन.....

पेज एक का शेष

गाने का शौकीन था अनिल जिंदल

एसआरएस ग्रुप का चेयरमैन अनिल उस महीने में कम से कम दो-तीन बार गाने की महफिल सजाता था। दिल्ली में रहने वाली एक प्रोफेशनल गायिका को जिंदल ने वेतन पर रखा हुआ था। बाद में वह उस गायिका को ही गाने के तरीके समझाने लगा और खुद गाकर बताता था कि किस तरह वह अपना सुर ताल ठीक कर सकती है। उस गायिका के एक एक बोल पर वह महफिल में पैसे लुटाता था। जिंदल से जुड़े प्रॉपर्टी डीलर, रियल्टी सेक्टर के अन्य दलाल, पुलिस व प्रशासनिक अफसर, छुटभैये नेता उन महफिलों की शोभा बढ़ाते थे।

बैंकों से ठगी का एक जैसा पैटर्न

चाहे वह रोटोमैक कंपनी द्वारा की गई ठगी हो या फिर विडियोकॉन के मालिक द्वारा बैंकों को लगाया चूना शामिल हो या फिर एसआरएस ग्रुप द्वारा बैंकों से लोन लेकर अमीर बनने की कहानी हो, सभी घोटालों में एक जैसा पैटर्न है। बैंक फ्रॉड के जितने भी मामले अभी तक खुले हैं, उनमें तमाम फर्जी धन्ना सेठों ने शेल कंपनियां बनाईं। इनके नाम पर बैंक लोन लिया। इन्हीं शेल कंपनियों में से एक दूसरे कंपनी को बैंक गारंटी भी देते रहे। यह पैटर्न हर जगह और तमाम शहरों में अपनाया गया। इसका निचोड़ यह निकलता है कि बैंकों के बड़े अफसरों ने या तो यह रास्ता दिखाया या फिर देश के बड़े चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने तमाम घोटालेबाजों को ऐसा कर पैसा कमाने की सलाह दी।

बैंकों से करोड़ों के लोन चुटकियों में लेने का खेल इतना आसान नहीं है। यह तभी संभव है जब आपकी राजनीतिक सेटिंग बहुत हाई लेवल पर हो और आप बैंकों के बड़े अफसरों को मोटा पैसा खिला सकें। यही काम देश से फरार हो चुके विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने किया और यही काम अनिल जिंदल ने भी किया। इन सभी ने सत्ता से करीबी बनाई, बैंक अफसरों को रिश्वत से लेकर सुरा सुंदरी तक पहुंचाई और रातोंरात अमीर बन बैठे।

एस.सी.-एस.टी एक्ट दलितों का नहीं शासकों का हथियार है

सतीश कुमार, सम्पादक मजदूर मोर्चा

यह सच्चाई मुझ से बेहतर कौन जान सकता है? दिनांक 5 अक्तूबर 2002 की शाम करीब 7-8 बजे जब मैं सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में चल रहे पुस्तक मेले से अपने स्कूटर पर सवार होकर निकल रहा था तो तत्कालीन चौटाला सरकार एवं एसपी फरीदाबाद रणबीर शर्मा के आदेश पर डीएसपी थावर सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ मुझे घेर लिया और उठा कर सीधे थाना सेंट्रल में ले गया।

वहां थावर सिंह नायब रीडर हवलदार रमेश के झूठे बयान पर मेरे विरुद्ध एस.सी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा नम्बर 813 दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। अगले दिन ड्रयूटी मैजिस्ट्रेट सुकरमपाल ने बिना कुछ सुने दो सप्ताह के लिये मुझे सोनीपत जेल भेज दिया। बाद में ज़िला बार एसोसिएशन (वकीलों) की पैरवी से अतिरिक्त सैशन जज ने जमानत मंजूर कर ली। मात्र दो सप्ताह की जेल यात्रा करके मैं बाहर आ गया।

सुनवाई करने वाले स्पेशल अतिरिक्त सैशन जज ने मुझे रिहा करते हुए पुनः तफ़्तीश करने के आदेश दिये। इस बीच जनता ने चौटाला का तख्ता पलट दिया। न रणबीर शर्मा एसपी रह पाये न थावर डीएसपी रह गये थे। अब तफ़्तीश तत्कालीन डीएसपी बदन सिंह राणा से कराई गयी। थावर सिंह द्वारा खड़े किये गये तमाम गवाह, एसएचओ सेंट्रल रणधीर सिंह समेत तमाम पुलिस वालों ने मेरे हक में बयान देते हुए केस को झूठा दर्ज होना बताया। लिहाजा मुकदमा रद्द करके अदालत में भेज दिया गया।

तत्कालीन एसी जेएम बुद्धि दिवाकर ने शिकायतकर्ता हवलदार रमेश को कई बार बुलाया। उसके न आने पर पुलिस रिपोर्ट पर अपनी अन्तिम मुहर लगाकर एफ़आईआर रद्द कर दी। इसके बावजूद न्यायपालिका का ड्रामा देखो जो अब तक बतौर शिकायतकर्ता रमेश बतौर प्राइवेट शिकायत डाल केस को घसीटे जा रहा है।

संदर्भवश पाठक जान लें कि चौटाला सरकार ने एसपी. रणबीर शर्मा के द्वारा डीएसपी थावर व हवलदार रमेश (दोनों चमारों) को मोहरा बना कर एससी-एसटी एक्ट का घोर दुरुपयोग किया था और इस बेकसूर पत्रकार को मुफ़्त में 2 सप्ताह की जेल यात्रा करा दी थी। इस केस में जमानत भी महज 2 सप्ताह में इस लिये हो पाई थी क्योंकि ज़िले के सारे जज साहेबान अगस्त 2001 से देख रहे थे कि चौटाला सरकार के इशारे पर रणबीर शर्मा (हत्या सहित) मेरे विरूद्ध 5 झूठे मुकदमे पहले भी दर्ज करा चुका था। इस लिये वे पुलिस फ़ाइलों की झूठ से पूर्णतया वाकिफ़ थे।

एस सी/एसटी एक्ट के तहत इसी तरह के अनेकों झूठे केस आये दिन देखने को मिलते हैं। सचमुच का पीड़ित दलित बेशक रोज़ाना गांव के दबंगों से प्रताड़ित होता रहे कोई उसकी सुनवाई नहीं करता। हां, जहां राजनेता, प्रशासन अथवा किसी से बदला लेने की बात हो तो ही एससी/एसटी रूपी इस हथियार का बेहद सटीक दुरुपयोग होता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस एक्ट पर हालिया फ़ैसले को लेकर जिस तरह पक्ष और विपक्ष ने तुमार बांध रखा है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो 1996 में कही अपनी उसी बात को तो दोहरा रही है कि बिना सबूतों के किसी को नाजायज गिरफ़्तार न किया जाय, जैसे 2002 में मुझे किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की इतनी कमजोरी जरूर है कि उसके आदेशों की खुली उल्लंघना करने वालों को वह उचित 'प्रसाद' नहीं देती। यदि इस तरह से उल्लंघन करने वाले 2-4 अफ़सरों को ठीक-ठाक सा प्रसाद मिल जाता तो मौजूदा आदेश देने की कोई जरूरत ही न पड़ती।

मेरे केस में गौरतलब यह भी है कि शिकायतकर्ता खुद एक पुलिस अफ़सर है। दलित जाति से बेशक हो, उसे सरकार ने लाठी व बंदूक के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता से भी लैस कर रखा है। इतना सब होने के बावजूद भी कोई दलित कैसे हो सकता है?

संबंधित खबरें पेज दो पर

भीड़ बहुत अच्छी है, अगर आपके पक्ष में खड़ी हो, भीड़ बहुत बुरी अगर आपके खिलाफ हो!

भीड़ जब आपके लिए लाठी और त्रिशूल भांजे तो आप अट्टाहास करते हैं। भीड़ जब आपके खिलाफ भारत बंद करवाने पर उतारू हो जाये तो आपके देश को होने वाले आर्थिक नुकसान की चिंता सताने लगती है।

दलितों के भारत बंद ने भारतीय राजनीति और समाज की कुछ भयावह सच्चाइयों को उजागर किया है। पहली बात यह कि संगठित आक्रमकता ही अपनी बात मनवाने का एकमात्र और स्वीकृत तरीका है।

याद कीजिये तमिलनाडु आकर जंतर-मंतर पर धरना दे रहे किसानो को। गले में खोपड़ी की माला, मुंह में मरे चूहे दबाये। पेशाब पीकर अपनी हालत बयान करते किसान। आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था। राष्ट्रीय मीडिया पर कवरेज शून्य था। सोशल मीडिया पर लोग तालियां पीट-पीटकर हंस रहे थे। किसान कई दिनों तक बैठे रहे और फिर वापस चले गये। उनकी मांगों का क्या हुआ किसी को पता नहीं है।

अब जाटों के आरक्षण आंदोलन को लीजिये। बस जलाई गईं। निर्दोष राहगीरों की हत्या की गई। बलात्कार तक के मामले सामने आये। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फौरन जाट भाइयों को बातचीत का न्यौता दिया। आश्वसान दिया गया कि सारे मुकदमे वापस लिये जाएंगे। उसके बाद यूपी चुनाव के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऑडियो आया- जाट नेताओं को पुचकारते, ऐतिहासिक संबंधों की दुहाई देते।

हार्दिक पटेल ने गुजरात में हिंसा फैलाई और रातो-रात हीरो बन गया। उसे मनाने की भरपूर कोशिशें हुईं। लेकिन मुकदमों की वजह से वह इस तरह बिदका कि कांग्रेस के पाले में चला गया। इस तरह हार्दिक पटेल देशद्रोही हो गया लेकिन हिंसक पाटीदार आंदोलन से जुड़े उसके जो साथी बीजेपी के साथ आये वे सब देशभक्त हो गये। 21वीं सदी सबसे बड़े गांधीवादी योगी आदित्यनाथ इस देश के नये पोस्टर ब्वाय हैं, जिन्हे हिंदू वाहिनी नाम का एक हथियारबंद दस्ता स्थापित करने का श्रेय जाता है। बाबाजी भारत के पहले ऐसे नेता हैं, जो सांवैधानिक पद पर बैठकर एक्स्ट्रा ज्यूडीशियल किलिंग को सबसे पवित्र काम के रूप में स्थापित कर रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। योगी जी पहले ऐसे नेता हैं, जिन्होने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने उपर लगे सारे आपराधिक मामले हटा लिये। दूसरी तरफ दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण का हाल भी सुन लीजिये। कानूनी दांव-पेंच में फंसाकर लगभग गैर-कानूनी तरीके से जेल में बंद किया गया है और अपाहिज हो चुका है। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जगह उसका नाम संगीत सोम होता तब भी उसकी यह हालत होती?

मरे हुए जानवर की खाल उतार रहे लोगो की खाल खींच ली जाती है। घोड़ी चढ़ने वालों की गर्दन काट दी जाती है और इस देश की सबसे बड़ी अदालत को लगता है कि एसटीएसी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। जातिवादी पूर्वाग्रह की जड़े इस देश में कल्पनाओं से भी ज्यादा गहरी हैं।

दलित आंदोलन के दौरान हुई हिंसा देखकर बहुत दुख हुआ। जब आप न्याय की मांग कर रहे हों तो कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि आचरण भी विधिसम्मत हो। हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हिंसा की चिंता इस देश में किसे है? गांधी की तरह चरखा कातते हुए फोटो खिंचवाने वाले प्रधानमंत्री ने समाज में बढ़ रही हिंसा के बारे में कितनी बार क्या बोला है यह याद कर लीजिये और याद आ जाये तो मुझे भी बता दीजियेगा।

- राकेश

नूर और अला, दो बहनें : सीरिया युद्ध के मासूम शिकार

बहनों ने 6 दिन पहले मदद मांगी थी।
रेडक्रॉस की टीम घोउटा से इदलिब लेकर आई
5 माह के 273 ट्वीट का मजमून
हम हर पल यहां मर रहे हैं, जिंदगी तहखानों में
दफन हो रही, कोई तो इसे रोके

हम नूर और अला हैं। 10 और 8 साल के हैं। घोउटा में रहते हैं। जो कुछ हम यहां देख रहे हैं वो युद्ध है। हम खेलना चाहते हैं। स्कूल जाना चाहते हैं और शांति से रहना चाहते हैं। हर दिन बमबारी, बमबारी और सिर्फ़ बमबारी...। हमें प्लेन से नफ़रत है। ये रोज़ाना बच्चे को मार रहे हैं। हमें आश्चर्य होता है कि इस बार कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दो साल का करीम अपनी दादी और पापा के साथ रहता है। दो दिन पहले हुई बमबारी में उसने पापा को खो दिया। बमबारी के चलते स्कूल बंद है। आज 45 दिन हो गए हैं। बच्चे तहखानों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन ये प्लेन तहखानों को भी तबाह कर देते हैं। यहां जिंदगी बद्तर होती जा रही है। बमबारी जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हर दिन कोई न कोई दम तोड़ रहा है। मेरे अरबी भाषा के टीचर भी मारे गये। प्लीज कोई इस पागलपन को रोके। हमारा घर भी तबाह हो गया। अला जख्मी हो गयी। हमारा घर छूट चुका है और हमारे सपने भी। हम अभी जोबार में है। मैं इस युद्ध को खत्म होते देखना चाहती हूं।

स्मार्ट सिटी की कल्पना

एक स्मार्ट सिटी की कल्पना को जब वास्तविकता का धरातल चाहिए तो इसमें एक ऐसे अस्पताल की कल्पना करती हूं जिसमें पिता की तानाशाही का इलाज मुफ़्त हो सके। और साथ ही इस तानाशाही का शिकार हो चली बेटियों के डिप्रेशन का भी इलाज हो। घरों में आये दिन लड़कियों के सपनों को कत्ल कर दिया जाता है, वहां स्मार्ट सिटी की कल्पना मेरे लिए न केवल कल्पना जगत का शहर है, बल्कि सरकारों की घोषणा वास्तविक ही नहीं लगती।

स्मार्ट शहर में ऐसा विद्यालय चाहिए जहां लड़का-लड़की के भेद को खत्म करके जमीन-जायदाद में बराबरी का हक देने की शिक्षा हो। ताकि मेरी जैसों की आंखे मुख्य सड़कों पर कूड़े के ढेरों को देख सकें और सड़कों के किनारे कहीं तरतीब में खड़ी साइकिलें देखकर मैं बेखौफ़ अपने जीवन का पहिया इस साइकिल में लगा के घूम सकूं। मुझे ऐसा स्मार्ट शहर चाहिए जिसमें इसके सभी नागरिक पान की दुकान पर खड़े होकर न केवल राजनीति की चर्चा करें बल्कि स्वच्छ भारत की कल्पना को हकीकत में बदलने को मजबूत हाथ हों। इस शहर में कुछ छोटे-छोटे पार्क हों जहां युवा प्यार के कुछ पल गुजार सकें और इन पार्कों में किसी भी राजनीति पार्टी के दफ़्तर ना हो, ऐसे पार्कों में किसी राजनीतिक जलसे की इजाजत ना हो, ताकि सड़कों पर कूड़े के ढ़ेर के बजाय बच्चों के खेल के खिलौने, गुब्बारे आराम से मिल सकें।

स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ यही कचरा हटाना नहीं होता!

-कुसुम, शोध छात्रा